IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

झारखंड राज्य में विधान सभा चुनाव (2024)में झामुमो की जीत और भाजपा की पराजय के प्रमुख कारक – एक समीक्षा

मिथिलेश कुमार माहथा
शोधार्थी , राजनीति विज्ञान विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड

सारांश (Abstract)

झारखंड विधानसभा चुनाव (2024) में झामुमो और इंडिया गठबंधन की जीत हुई। हेमंत सोरेन की जीत की आंधी में एनडीए उड़ गया। झामुमो 34 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है और इंडिया गठबंधन 56 सीटों पर मिली जीत के साथ सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरी है। भाजपा को 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। एनडीए गठबंधन के पास 24 सीटें हैं। हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार सीएम बने। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार इंडिया गठबंधन के ग्राफ में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कांग्रेस, राजद और माले का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। संताल परगना, कोल्हान, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल में इंडिया गठबंधन की मजबूत पकड़ रही. झारखंड ने दूसरी बार राज्य में गठबंधन को बहुमत की सरकार दी है।

मूल शब्द : विधानसभा,भाजपा, झामुमो, गठबंधन चुनाव, बहुमत

विषय प्रवेश – झारखंड विधानसभा के सभी 81 सदस्यों को चुनने के लिए वर्ष 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव 13 से 20 नवंबर 2024 तक दो चरणों में आयोजित किए गए थे।[1] मतों की गिनती 24 नवंबर 2024 को हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 23.44% मत प्राप्त करते हुए 34 सीटें जीतीं और उसके गठबंधन, महागठबंधन (इंडिया ब्लॉक), जिसमें कांग्रेस, सीपीआई (एमएल) एल और आरजेडी शामिल थे, ने 44.37% मत प्राप्त करते हुए 56 सीटें जीतीं। भारतीय जनता पार्टी ने 33.18% मत प्राप्त करते हुए 21 सीटें जीतीं और उसके गठबंधन, एनडीए ने 38.14% मत प्राप्त करते हुए 24 सीटें जीतीं। झारखंड विधानसभा की पांचवीं बैठक का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव नवंबर–दिसंबर 2019 में हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई, जिसमें हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने ।

तालिका
झारखण्ड विधानसभा चुनाव (2024)

मतदान कार्यक्रम	चरण	
	प्रथम	द्वितीय
अधिसूचना दिनांक	18 अक्टूबर	22 अक्टूबर
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि	25 अक्टूबर 2024	29 अक्टूबर 2024
नामांकन की जांच	28 अक्टूबर	30 अक्टूबर
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	30 अक्टूबर	1 नवंबर
मतदान की तिथि	13 नवंबर	20 नवंबर
मतों की गिनती की तिथि	23 नवंबर	
निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	43	38

स्रोत :[2] http//eci.gov.in

13 नवंबर 2024 को हुए पहले चरण के मतदान में, 15 जिलों में फैले 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जहां 638 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। कुल मतदान प्रतिशत 66.65% रहा। जहां 69.04% महिला मतदाताओं ने ईवीएम का बटन दबाया, वहीं पुरुषों का प्रतिशत 64.27% रहा और केवल 31.02% महिलाओं ने मतदान किया। पहले चरण में मतदान करने वाले 43 में से 37 क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। खरसावां विधानसभा में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत 77.32% दर्ज किया गया। इसके बाद बहरागोरा (76.15%) और लोहरदगा (73.21%) का स्थान रहा। हालांकि, रांची में सबसे कम मतदान हुआ, जहां केवल 51.5% मतदाताओं ने ही चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया।[3]

20 नवंबर 2024 को हुए दूसरे चरण के मतदान में झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। उम्मीदवारों की संख्या 528 थी। झारखंड की इन 38 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत 68.45% रहा। लोकनीति के चुनावोत्तर सर्वेक्षण के अनुसार, इंडिया गठबंधन की मैया सम्मान योजना, जिसमें शुरुआत में आरएस1,000 और बाद में बढ़ाकर आरएस 2,500 दिए गए, को पंजीकृत महिला मतदाताओं में से 47% का समर्थन मिला, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके विपरीत, भाजपा की गोगो दीदी योजना, जिसमें आरएस 2,100 दिए गए, शहरी महिला मतदाताओं के बीच अधिक लोकप्रिय रही। कुल मिलाकर, महिलाओं ने भाजपा (38%) की तुलना में इंडिया गठबंधन (45%) को अधिक समर्थन दिया, जिसमें ग्रामीण महिलाएं (48%) और आदिवासी महिलाएं (60%) इंडिया गठबंधन के पक्ष में अधिक रहीं। हालांकि, भाजपा ने शहरी और गैर–आदिवासी महिला मतदाताओं के बीच बेहतर प्रदर्शन किया। एक उल्लेखनीय परिणाम यह रहा कि भाजपा को केवल एक अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट मिली।[4]

तालिका
चुनाव पश्चात सर्वेक्षण

मतदान एजेंसी	एनडीए	एमजीबी	अन्य	नेतृत्व करना
एक्सिस माई इंडिया	17–27	49–59	1–6	एमजीबी
लोगों की अंतर्दृष्टि	42	33	6	एनडीए
चाणक्य रणनीतियाँ	45–50	35–38	3–5	एनडीए
दैनिक भास्कर	37–40	36–39	0–2	त्रिशंकु
चुनावी बढ़त	32	42	7	एमजीबी
मैट्रिक्स	42–47	25–30	1–4	एनडीए
पी मार्क	31–40	37–47	6–8	एमजीबी
टाइम्स नाउ – जेवीसी	40–44	30–40	1	एनडीए
लोगों की नब्ज़	44–53	25–37	5–9	एनडीए

स्रोतः[5] ई–पेपर प्रभात खबर, राँची

मतदान मुख्यतः स्थानीय मुद्दों और विशेषताओं पर ही केंद्रित रही। झारखंड के वोटर केंद्र और राज्य सरकारों के प्रति अपने आकलन में सकारात्मक थे। बल्कि केंद्र सरकार के प्रति मतदाताओं की संतुष्टि तुलनात्मक रूप से थोड़ी ज्यादा ही थी। अगर दोनों सरकारों के प्रति मतदाताओं की कुल संतुष्टि की तुलना करें, तो केंद्र सरकार के प्रति मतदाताओं की संतुष्टि राज्य सरकार की तुलना में छह प्रतिशत ज्यादा थी। केंद्र सरकार के प्रति पूर्णतः संतुष्ट दो–तिहाई वोटरों ने (68 प्रतिशत) एनडीए गठबंधन को मत दिया। दूसरी तरफ, केंद्र सरकार से पूरी तरह असंतुष्ट मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को मत दिया।[6] जहां तक राज्य सरकार की बात है, तो उससे पूरी तरह संतुष्ट मतदाताअें में से दो–तिहाई मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को मत दिया, जबकि राज्य सरकार से पूरी तरह असंतुष्ट मतदाताओं में से दो–तिहाई ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में मत दिया. इससे यह संभावना बनती है कि मतदाता प्रारूप का आधार ठोस कारण और सरकारों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मतदाताओं ने पहले से ही मन बना लिया था कि किसे मत देना है। फिर एक बार झामुमो भाजपा के रास्ते की बाधा बनी। हालांकि चुनावी नतीजा तो विजयी और पराजित प्रत्याशियों के ब्योरे में मिलेगा, लेकिन झारखंड ने जो व्यापक तस्वीर पेश की, उसके दो प्रधान तत्व हैं. पहला राज्य स्तरीय शक्तियों का पूरी क्षमता और दृढ़ता से अखिल भारतीय अतिक्रमण का मुकाबला करना और उसे रोकना, और दूसरा आदिवासी अस्मिता पर केंद्रित क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित अखिल भारतीय आक्रामक अभियान के, जिसका लक्ष्य आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करना था, बीच कड़ा

मुकाबला. झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन की प्रभावी जीत रणनीतिक स्तर पर प्रभावी गठबंधन प्रबंधन और अभियान की जीत है। झामुमो नीत सरकार अपने प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड और आदिवासी हितों को सुरक्षित रखने की अपनी छवि की रक्षा कर रही थी। दूसरी ओर, भाजपा नीत गठबंधन ने एक व्यापक विमर्श पेश करने की कोशिश की, जो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अलावा उसने सत्तारूढ़ सरकार की काहिली और भारी भ्रष्टाचार पर तीव्र हमला बोला. भाजपा के विमर्श में हिंदूत्व को जगाने की आक्रामक रणनीति भी थी।

झामुमो गठबंधन न सिर्फ अपना आदिवासी वोट बैंक बचाने में सफल रहा, बल्कि कांग्रेस के साथ मिलकर उसने गैर आदिवासी इलाकों में भी पैठ बढ़ायी। भाजपा ने गैर–आदिवासी इलाकों में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आदिवासी इलाकों में उसकी मजबूत पकड़ नहीं बन पायी। विजयी गठबंधन में झामुमो निश्चित तौर पर नेतृत्वकारी भूमिका में रहा और उसकी जीत का आंकड़ा 80 फीसदी रहा। गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका जूनियर पार्टनर की रही और उसकी जीत का आंकड़ा 50 फीसदी से थोड़ा ही अधिक रहा। इंडिया गठबंधन में जहां तमाम दलों के बीच बेहतर तालमेल था और जिसे राज्य के सभी क्षेत्रों से समर्थन मिला, वहीं एनडीए गठबंधन ज्यादातर भाजपा पर निर्भर था। इंडिया गठबंधन के साथियों के बीच सीटों का बेहतर वितरण हुआ, जबकि एनडीए में हर 10 सीटों में से सात पर भाजपा लड़ रही थी. इंडिया गठबंधन में सभी साथियों के साझा संदेश का उनको लाभ मिला। मतदाताओं के सभी आयु वर्गों के बीच इसे समर्थन मिला। ग्रामीण इलाकों में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। गरीब, मध्य वर्ग और कम पढ़े–लिखे मतदाताओं का समर्थन इसके साथ था. अनुचित जातियों–जनजातियों, मुस्लिमों तथा यादवों का इसे समर्थन मिला इसके सामाजिक गठजोड़ का पता इसमें शामिल झामुमो, कांग्रेस, राजद तथा कम्युनिस्ट पार्टियों को देखकर चलता है।

राज्य के मतदाताओं के बीच के तीव्र ध्रुवीकरण हुआ है। हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट दो तिहाई मतदाताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में मत दिया।[7] दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन के कामकाज से असंतुष्ट दो तिहाई लोगों ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में मत दिया. इससे साफ है कि संतुष्टि से ज्यादा मतदाताओं द्वारा पहले से एक गठबंधन के पक्ष में मत देने के फैसले से यह परिणाम आया. हालांकि सोरेन सरकार की तुलना में मोदी सरकार के प्रति कुल संतुष्टि ज्यादा थी, लेकिन झामुमो के प्रति मतदाताओं के समर्थन ने मतदान प्रणाली को प्रभावित किया। राज्य के मतदाता जमीनी स्तर पर सरकार के विकास कार्यक्रमों से बहुत संतुष्ट नहीं थे। वे यह मान रहे थे कि पिछले पांच वर्षों में उद्योगों के स्तर पर स्थिति खराब हुई है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। जबकि सांप्रदायिक हिंसा और नक्सलवाद के मोर्चे पर हालत में सुधार आया है. पर जिन लोगों ने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और विकास के अभाव की चर्चा की, उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मत दिया. दूसरी बात यह कि महिला मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को तरजीह दी. जिस एक और तत्व ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में भूमिका निभायी, वह दर असल मतदाताओं की यह सोच थी कि इस चुनाव में झारखंड राज्य का मुद्दा सबसे बड़ा है। एनडीए गठबंधन के समर्थन में आये राष्ट्रीय नेताओं का भी चुनावी नतीजे पर असर पड़ा। एनडीए गठबंधन को मत देने वालों में से ज्यादातर ने नरेंद्र मोदी की भूमिका को रेखांकित किया। ऐसे ही, इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों ने राहुल गांधी के असर को स्वीकारा. सर्वे में शामिल लोगों में से एक तिहाई हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते थे. इस तरह भाजपा जहां नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर पूरी तरह निर्भर था, वहीं इंडिया गठबंधन में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे।

इस तरह इंडिया गठबंधन की जीत आदिवासी इलाकों में झामुमो के और गैर आदिवासी इलाकों में उसकी सहयोगी पार्टियों के असर के कारण संभव हुई। जनसांख्यिकी के विभिन्न पैमाने पर इंडिया गठबंधन का समर्थन एनडीए से अधिक था। बेशक सत्तारूढ़ गठबंधन के दौर में भ्रष्टाचार की बात उभर कर सामने आयी, लेकिन दूसरे वोटिंग पैटर्न के हावी होने के कारण इंडिया गठबंधन सत्ता में दोबारा वापस आया. भाजपा ने समान नागरिक संहिता और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दों पर मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने की कोशिश की, लेकिन राज्य के मतदाताओं पर स्थानीय मुद्दों का असर ज्यादा था, जो कि सरना पहचान पर मतदाताओं की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है। संताल समुदाय को छोड़कर भाजपा राज्य के और किसी आदिवासी समुदाय को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पायी।[8] दीर्घावधि में भाजपा के सामने इस राज्य के आदिवासियों को अपने पक्ष में एकजुट करने की चुनौती रहेगी. इसे साधने के अलावा राज्य में हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे पाने में उसकी सफलता से ही झारखंड में भविष्य का राजनीतिक मुकाबला तय होगा।

राज्य में औद्योगिकीकरण के मुद्दे पर सर्वे में शामिल लोगों की प्रतिक्रिया उदासीनता भरी थी. वे यह मान रहे थे कि पिछले पांच साल में राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है। उनका यह भी आकलन था कि सांप्रदायिक हिंसा और नक्सल हमलों में कमी आयी है। उनका यह भी मानना था कि राज्य में धार्मिक सद्भाव पहले की ही तरह बना हुआ है। के सिवाय दूसरे प्रमुख मुद्दों पर सर्वे में शामिल लोगों के संतुष्ट करने वाले जवाब से राज्य में झामुमो के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जीत को समझा जा सकता है। सर्वे ने बढ़ती महंगाई और रोजगार के कम होते अवसरों के प्रति लोगों के क्षोभ को भी इंगित किया। पेयजल उपलब्धता, सड़कों की दशा, सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा सुविधा की उपलब्धता और महिला सुरक्षा के मोर्चे पर सुधार के मामले में ज्यादातर लोगों ने कहा कि स्थिति बेहतर हुई है या जस की तस है। इस तरह, भ्रष्टाचार को छोड़कर, सोरेन सरकार को लेकर वोटरों की कम नकारात्मक सोच ने ही उसे दोबारा सत्ता में आने का अवसर प्रदान किया।

केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों ने देश के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि यह भी सच है कि इनमें से कई योजनाएं चुनावी लाभ के उद्देश्य से शुरू और लागू की गयी हैं। विदित हो कि राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और स्वयं द्वारा शुरू की गयी कल्याणकारी योजनाओं, दोनों को लागू करने का अधिकार है। हालांकि झारखंड के मामले में, इन योजनाओं की लोगों तक पहुंच में बड़े पैमाने पर भिन्नता दिखाई देती है। केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें, तो जहां पीडीएस ने 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं (रेस्पॉन्डेंट) को लाभान्वित किया है, वहीं मनरेगा और आवास योजना ने क्रमशः 22 प्रतिशत और 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लाभान्वित किया है. राज्य सरकार की योजनाओं की लोगों तक पहुंच केंद्र सरकार की योजनाओं की तुलना में कम रही है और इन योजनाओं में मुफ्त बिजली योजना अन्य योजनाओं की तुलना में कहीं अधिक लोगों तक पहुंची है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या में अंतर योजनाओं के डिजाइन, लाभार्थियों की रुचि और कार्यान्वयन प्राधिकरण की सक्रियता में भिन्नता के कारण आया है। यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि उत्तरदाताओं को इस बात की जानकारी थी कि किस सरकार ने कौन सी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इस कारण अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को शुरू करने का श्रेय केंद्र सरकार को दिया गया है, जबकि राज्य सरकार की योजनाओं का श्रेय राज्य सरकार को दिया गया है। यहां एक बात जो महत्वपूर्ण है, वह यह कि भले ही किसी भी सरकार (राज्य या केंद्र सरकार) ने कल्याणकारी योजना शुरू की हो, लाभार्थियों के एक बड़े प्रतिशत ने मौजूदा राज्य सरकार, (आइएनडीआइ गठबंधन) के पक्ष में ही मतदान किया है। हालांकि, आइएनडीआइ गठबंधन और एनडीए

को जिन्होंने वोट दिया है, उनके बीच अंतर की बात करें, तो यहां केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की तुलना में राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है। यदि गैर–लाभार्थियों की बात करें, तो केंद्र और राज्य सरकार की अधिकांश योजनाओं के गैर–लाभार्थियों ने भी इंडिया गठबंधन को मत दिया है। पीडीएस, मुफ्त बिजली और अबुआ आवास योजना को छोड़ कर, केंद्रीय और राज्य सरकार की अन्य सभी योजनाओं के गैर–लाभार्थियों के एक बड़े प्रतिशत ने एनडीए की तुलना में आइएनडीआइ गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। हालांकि उनमें से, आइएनडीआइ और एनडीए को वोट देने वालों के बीच का अंतर लाभार्थियों के मामले में कम रहा है।

झारखंड में झामुमो और उसके सहयोगियों के खिलाफ बनी सत्ता–विरोधी भावना का लाभ उठाने के लिए भाजपा ने अपने चुनाव अभियान में विविध तर्क गढ़े और कई रणनीति अपनायी। भाजपा अल्पसंख्यकों को अंधेरे में रखकर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना चाहती थी. झारखंड के अपने घोषणापत्र में हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने समान नागरिक संहिता का वादा किया था। पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत से ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा के भाषण बांग्लादेशी घुसपैठियों पर केंद्रित थे। यह कहा गया कि ये घुसपैठिये स्थानीय लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। ''बंटेंगे तो कटेंगे'' का नारा और लव जिहाद का जिक्र भी भाजपा के चुनाव अभियान का हिस्सा थे।[9] ये मुद्दे चुनाव में जीत के लिए पर्याप्त नहीं थे, इन मुद्दों ने राज्य के मतदाताओं पर कितना असर डाला। झारखण्ड के लोग समान नागरिक संहिता (यूसीसी) वाले भाजपा के वादे से अवगत थे. इस वादे से अवगत रहने वाले और अवगत न रहने वाले मतदाताओं के बीच 11 फीसदी का फर्क था, जो भाजपा के पक्ष में गया. जो लोग इस मुद्दे से अवगत थे, उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो माना ही, बड़ी संख्या में (55 फीसदी) भाजपा के पक्ष में वोट भी दिया। जहां तक बांग्लादेशी घुसपैठियों के संवेदनशील मामले की बात है। तो भाजपा ने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर वह सख्ती से निपटेगी। एक सर्वे में शामिल लोगों में से 40 फीसदी से अधिक भाजपा के इस दावे पर आश्वस्त थे। हालांकि भाजपा को इस मुद्दे पर कहीं ज्यादा (61 प्रतिशत) वोट मिले. अलबत्ता हिंदू मतदाताओं को सीधे या परोक्ष रूप से गोलबंद करने के उसके इन दोनों ही प्रयासों को झारखंड में सीमित सफलता मिली। सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन को परास्त करने के बजाय इसके जरिये भाजपा के वोट शेयर में कुछ इजाफा हुआ।

झारखंड में झामुमो और उसके सहयोगी दलों के अच्छे प्रदर्शन में कई कारकों का योगदान रहा है। झारखंडी पहचान और आदिवासी संस्कृति की वकालत करने वाले अभियान से उत्साहित होकर झामुमो ने आदिवासी न्याय, संस्कृति और भूमि अधिकारों के संरक्षक के रूप में अपनी दीर्घकालिक भूमिका की पुष्टि की। इसके विपरीत, भाजपा का अभियान जमाई जिहाद, जमीन जिहाद और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठ के आरोप के साथ आदिवासी भूमि अधिग्रहण और अंतर–सामुदायिक विवाह जैसे विभाजनकारी आख्यानों पर आधारित था। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने का वादा करते हुए। भाजपा मतदाताओं से प्रभावी ढंग से जुड़ने के लिए संघर्ष करती रही। बीते पांच वर्षों में, आदिवासियों को हिंदुत्व के दायरे में शामिल करने के इसके प्रयासों और इसकी कॉरपोरेट समर्थक नीतियों जिन्हें अक्सर आदिवासी भूमि और संसाधनों का शोषण करने वाला माना जाता है– ने समुदाय को भाजपा से कहीं अधिक दूर कर दिया है। जबकि झामुमो के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने कहीं अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया, (जिनमें से एक है) अधिवास स्थिति (डोमिसाइल स्टेटस) निर्धारित करने के लिए 1932 के सर्वेक्षण के आधार पर भूमि रजिस्ट्रियों को लागू करने का वचन देना। यह एक ऐसा कदम रहा, जो मतदाताओं के स्वर के साथ स्वर मिलाता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि झारखंड में पड़ोसी राज्यों से पलायन के इतिहास को देखते और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए। गठबंधन ने अभियान के दौरान पूरी सावधानी बरती है चुनावों में मतदाताओं के बीच झामुमो का गहरा प्रभाव रहा है। झामुमो को भाजपा की तुलना में

आदिवासी संस्कृति और झारखंडी पहचान के बेहतर रक्षक के रूप में देखा गया। आदिवासी मतदाताओं का मानना था कि झामुमो उनकी इन प्राथमिकताओं को सुरक्षित रखने के लिए सबसे उपयुक्त है, जबकि केवल एक चौथाई ने भाजपा पर उसी तरह का विश्वास व्यक्त किया। भूमि अधिकार की बात करें, तो सभी मतदाताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर भाजपा को हालांकि थोड़ी ही सही पर बढ़त हासिल हुई, परंतु इस मुद्दे पर भी आदिवासी मतदाताओं ने झामुमो पर ही अत्यधिक भरोसा जताया। कुल मिलाकर देखें, तो मतदाताओं को इंडिया गठबंधन झारखंड की सत्ता सौंपने के लिए पूरी तरह उपयुक्त लगा और उन्होंने इसे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से अधिक पसंद किया (तीन प्रतिशत अंक क्रमशः 36 प्रतिशत बनाम 33 प्रतिशत)। यह चुनाव इस बात की पुष्टि करता है कि झारखंड में राजनीतिक सफलता स्थानीय पहचान और आदिवासी चिंताओं के साथ जुड़ने पर ही निर्भर है। मतदाताओं के साथ झामुमो का मजबूत जुड़ाव एक ऐसे नेतृत्व के प्रति उनकी चाहत को दर्शाता है जो उनकी संस्कृति, भूमि और भविष्य की रक्षा करता है।[10]

संस्कृति, पहचान और भूमि अधिकार के मुद्दों पर औसत मतदाता की तुलना में आदिवासी मतदाता झामुमो की ओर अधिक आकर्षित हैं । इसे निम्नलिखित तालिकाओं में स्पष्ट किया गया है –

तालिका

कौन सी पार्टी बेहतर है

	जेएमएम	**भाजपा**	**दोनों**	**कोई भी नहीं**
आदिवासी संस्कृति की रक्षा				
कुल मतदाता	**38**	**31**	**11**	**09**
आदिवासी मतदाता	57	27	06	03
झारखंडी पहचान को बढावा				
कुल मतदाता	37	31	13	08
आदिवासी मतदाता	56	23	05	04
भूमि अधिकारों की रक्षा				
कुल मतदाता	31	34	11	09
आदिवासी मतदाता	**43**	**28**	**07**	**04**

इंडिया गठबंधन एक बेहतर सरकार के रूप में देखा गया

कौन सा गठबंधन झारखण्ड में शासन के लिए बेहतर साबित होगा	**प्रतिशत**
इंडिया	36
एनडीए	33
कोई भी नहीं	06

स्रोत :–[11] ई–पेपर प्रभात खबर, राँची

झामुमो के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को झारखंड में शानदार जीत हासिल करने में किस कारण मदद मिली, इसे लेकर कई तरह की व्याख्या की गयी है। परंतु एक ऐसा आख्यान है, जिसके बारे में आगे आकर बताया जाना जरूरी है कि कैसे आर्थिक रूप से कमजोर मतदाताओं ने झारखंड के मतदाताओं की मुर्तदान प्राथमिकताओं को आकार दिया, भले ही यह राज्य

खनिज संसाधनों से समृद्ध है, फिर भी लोगों का एक बहुत बड़ा वर्म यहां गरीब है। कि झारखंड में हर चार मतदाताओं में से एक आदिवासी समुदाय से आता है। गरीबों की एक बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय से भी आती है यहां के मतदान प्रारूपों में बड़ा विभाजन रहा। जहां गरीब और निचले वर्ग का ध्रुवीकरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा, वहीं उच्च वर्ग के मतदाताओं ने एनडीए सहयोगियों के लिए मतदान किया। आर्थिक रूप से गरीब मतदाताओं के बीच इंडिया गठबंधन ने एनडीए पर 11 प्रतिशत अंकों की बढ़त हासिल की। जबकि निम्न आय वर्ग के मतदाताओं के बीच, इंडिया गठबंधन ने एनडीए पर नौ प्रतिशत अंकों की बढ़त हासिल की. मध्यम वर्ग के मतदाताओं के बीच इंडिया गठबंधन की बढ़त घटकर मात्र तीन प्रतिशत अंक रह गयी, जबकि उच्च वर्ग के मतदाताओं के बीच इंडिया गठबंधन एनडीए से 25 प्रतिशत अंकों के भारी अंतर से पिछड़ गया उच्च वर्ग के मतदाताओं के बीच महत्वपूर्ण बढ़त के बावजूद एनडीए झारखंड में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी क्योंकि कुल मतदाताओं में से (सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार), 35 प्रतिशत आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के हैं, 28 प्रतिशत निम्न आय वर्ग से हैं, 30 प्रतिशत मध्यम वर्ग के हैं, जबकि मात्र सात प्रतिशत ही उच्च आय वर्ग की श्रेणी में आते हैं। एक ऐसे राज्य में, जहां का 75 प्रतिशत क्षेत्र ग्रामीण है, झामुमो ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत होकर उभरी, जिसने इंडिया गठबंधन को ठोस जीत दर्ज करने में सहायता की। ग्रामीण मतदाताओं के बीच इंडिया गठबंधन को 47 प्रतिशत वोट मिले, जबकि एनडीए गठबंधन को 37 प्रतिशत वोट मिले, जिसने 10 प्रतिशत अंक की भारी बढ़त दिलाई. हालांकि, शहरी मतदाताओं के बीच एनडीए ने इंडिया गठबंधन पर छह प्रतिशत अंक की बढ़त बनायी। इसे निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका

वर्गवार वोट

दलों को मिले वोट (%में)

	इंडिया	एनडीए
गरीब	49	38
निम्न आय वर्ग	46	37
मध्यम वर्ग	40	37
धनी	28	53
		नोट : बाकियों ने अन्य दलों को वोट किया।

स्रोतः[12] ई–पेपर प्रभात खबर, राँची

ग्रामीण मतदाताओं के बीच इंडिया आगे रही, एनडीए को शहरी मतदाताओं का समर्थन मिला–

विधानसभा चुनाव 2024 में दल को मिले वोट (%में)

	इंडिया	एनडीए
ग्रामीण	**47**	**37**
शहरी	36	42

स्रोतः[13] ई–पेपर प्रभात खबर, राँची

चुनाव प्रचार में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव में भाजपा के सह–प्रभारी हिमंता विस्व सरमा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, दोनों ने अपने चुनाव अभियान में झारखंड में डबल इंजन सरकार की जरूरत बतायी थी। उन्होंने जोर देते हुए

कहा था कि इस आदिवासी बहुल राज्य में तेज विकास और समृद्धि के लिए यह आवश्यक है। डबल इंजन के विमर्श पर भाजपा के अत्यधिक जोर देने के बावजूद पार्टी राज्य के वोटरों को इस बारे में प्रभावित करने में विफल रही। लोकनीति–सीएसडीएस के हाल ही में किये गये चुनाव बाद सर्वे में यह जानने की कोशिश की गयी कि क्या झारखंड के मतदाताओं को लगता था कि राज्य के विकास के लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत है. इस अध्ययन में यह भी जानने की कोशिश की गयी है कि इस आदिवासी राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में से किसके कामकाज ने मतदाताओं को प्रभावित किया।

परन्तु सवाल यह है कि क्या झारखंड के विकास के लिए केंद्र और राज्य में एक ही सरकार का होना जरूरी है? प्रदेश के मतदाताओं के विचार जरूर विभाजित रहे। लेकिन इनका बड़ा हिस्सा (46 फीसदी) मानता था कि यह जरूरी नहीं है। जबकि 40 प्रतिशत ने माना कि यह जरूरी है। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर मतदाताओं की राय इस पर निर्भर थी कि वे किस पार्टी का समर्थन करते हैं. इंडिया गठबंधन के समर्थकों में से आधे से अधिक मतदाताओं ने कहा कि राज्य के विकास के लिए डब डबल इंजन सरकार का होना जरूरी नहीं है. झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा (जेकेएलएम) के ज्यादातर समर्थक और दूसरी पार्टियों के भी आधे से अधिक समर्थक भी इस बात से सहमत थे। जब मतदाताओं से पूछा गया कि इस चुनाव में झारखंड में किसके कामकाज को वे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पांच में से दो लोगों ने राज्य के कामकाज को, तो 10 में से तीन लोगों ने केंद्र के कामकाज को महत्त्वपूर्ण बताया. जबकि हर पाँच में से एक मतदाता ने दोनों के कामकाज की महत्वपूर्ण बताया. यह सोच उनकी वोटिंग पैटर्न में भी दिखी। राज्य के काम को महत्वपूर्ण बताने वालों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, जबकि केंद्र के काम को महत्वपूर्ण बताने वालों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया। इसके अतिरिक्त, जो लोग दोनों सरकारों के काम को महत्वपूर्ण मानते थे, उनमें 11 फीसदी बढ़त इंडिया गठबंधन की रही। चुनाव बाद सर्वेक्षण बताता है कि डबल इंजन सरकार के मामले में वोटरों की राय बेशक विभाजित थी, लेकिन इनमें बहुमत वोटरों का मानना था कि डबल इंजन सरकार जरूरी नहीं है। डबल इंजन सरकार पर भाजपा के जोर देने के बावजूद मतदाताओं ने झामुमो के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को तरजीह दी और इसने एनडीए गठबंधन की हार में निर्णायक भूमिका निभायी।

डबल इंजन सरकार का राय तालिका

डबल इंजन सरकार का समर्थन

	जरूरी	गैरजरूरी (प्रतिषत में)
कुल	40	16
इंडिया गठबंधन के मतदाता	31	53
एनडीए गठबंधन के मतदाता	58	35
जेकेएलएम के मतदाता	28	51
दूसरी पार्टियों के मतदाता	23	56

नोट : शेष वोटरों ने जबाव नहीं दिया।

स्रोतः[14] ई–पेपर दैनिक जागरण, राँची

तालिका

केन्द्र या राज्य : किसके मत में किसके काम की भूमिका रही

केन्द्र या राज्य किसके मत में		पार्टी को मिले वोट (फीसदी) में		
किसके काम की भूमिका रही	कुल (% में)	इंडिया	एनडीए	अन्य
राज्य सरकार	41	66	24	10
केन्द्र सरकार	30	18	70	12
दोनों	18	43	32	25
कोई नहीं	6	24	11	65

नोट : शेष वोटरों ने जबाव नहीं दिया

स्रोतः[15] ई–पेपर दैनिक जागरण, राँची

सरकारी योजनाओं के लाभर्थियों और गैर–लाभार्थियों का मतदान प्रारूप

		दलों को मिले वोट (%)	
		इंडिया	**एनडीए**
केन्द्र सरकार की योजनाएं			
पीडीएस	लाभार्थी (67 प्रतिषत)	47	36
	गैर–लाभार्थी (28 प्रतिषत)	39	41
उज्जवला योजना	लाभार्थी (49 प्रतिषत)	45	37
	गैर–लाभार्थी (46 प्रतिषत)	43	39
आयुष्मान भारत	लाभार्थी (38 प्रतिषत)	47	38
	गैर–लाभार्थी (57 प्रतिषत)	43	38
आवास योजना	लाभार्थी (27 प्रतिषत)	49	39
	गैर–लाभार्थी (68 प्रतिषत)	43	37
मनरेगा	लाभार्थी (22 प्रतिषत)	51	38
	गैर–लाभार्थी (71 प्रतिषत)	43	38
राज्य सरकार की योजनाएँ			
मुफत बिजली योजना	लाभार्थी (55 प्रतिषत)	50	34
	गैर–लाभार्थी (40 प्रतिषत)	36	43
अबुआ आवास योजना	लाभार्थी (21 प्रतिषत)	60	26
	गैर–लाभार्थी (75 प्रतिषत)	40	41
विवाह सहायता योजना	लाभार्थी (9 प्रतिषत)	54	33
	गैर–लाभार्थी (82 प्रतिषत)	43	38
विवाह सहायता योजना (विवाह के लिए 30,000 रूपये की वित्तीय सहायता)			
	लाभार्थी (9 प्रतिषत)	54	33

	गैर–लाभार्थी (82 प्रतिषत)	43	38
चिकित्सा सहायता योजना (पंजीकृत कामगारों के लिए चिकित्सा सहायता)			
	लाभार्थी (8 प्रतिषत)	55	36
	गैर–लाभार्थी (81 प्रतिषत)	43	38
राज्य पेंशन योजना	लाभार्थी (29 प्रतिषत)	52	35
	गैर–लाभार्थी (66 प्रतिषत)	41	39

स्रोतः[16] ई–पेपर दैनिक जागरण, राँची

झारखण्ड विधानसभा चुनाव (2024) के राजनीतिक दलों को प्राप्त विधानसभा क्षेत्र

झामुमो :राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका, जामा, मधुपुर, सारठ, गिरिडीह,गोमिया,चंदनकियारी,टुंडी,घाटशिला,पोटका, ईचागद, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, सिसई, बिशुनपुर,भवनाथपुर, गांडेय, बहरागोड़ा, जुगसलाई, सिल्ली, गुमला – **34 सीट**

कांग्रेस : पाकुड़, जामताड़ा, पोड़ैयाहाट, महागामा, रामगढ़, बेरमो, बोकारो, जगन्नाथपुर, खिजरी, कांके, मांडर, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, छत्तरपुर, सिमडेगा –**16 सीट**

राजद : देवघर, गोड्डा, बिश्रामपुर, हुसैनाबाद– **04 सीट**

माले : सिंदरी, निरसा– **02 सीट**

भाजपा : जरमुंडी, कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, बगोदर, जमुआ, धनबाद, झरिया, बाघमारा, जमशेदपुर पूर्वी, सरायकेला, रांची, लातेहार, पांकी, डालटनगंज, गढ़वा, धनवार, हटिया – **21 सीट**

आजसू : मांडू – 01 सीट

जदयू : जमशेदपुर पश्चिम **– 01 सीट**

जेएलकेएम : डुमरी **– 01 सीट**

झारखंड में ''इंडिया गठबंधन'' की आंधी चली।[17] झारखंड में पहली बार किसी गठबंधन को इतना प्रचंड बहुमत मिला. 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा में ''इंडिया गठबंधन'' 56 सीटें जीतकर आया है. इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का रिकॉर्ड भी बना दिया है. झारखंड का यह जनादेश झामुमो के लिए कई सौगात लेकर आया. । झामुमो ने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार इतना बड़ा प्रदर्शन किया है. झामुमो को अकेले 34 सीटें आयीं हैं। वहीं, कांग्रेस ने 16 सीटों वाला अपना पुराना स्ट्राइक रेट बरकरार रखा है. इंडिया गठबंधन में राजद ने चार और माले ने दो सीटों पर जीत कर गठबंधन को मजबूत किया। इस चुनाव में हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर, बैजनाथ राम, बन्ना गुप्ता और बेबी देवी चुनाव हार गये। वहीं, मंत्री रहे डॉ रामेश्वर उरांव, दीपक विरुआ, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी और हफीजुल हसन ने चुनाव जीत कर अपनी साख बचायी। झारखंड ने अपने जनादेश से एनडीए की कमर तोड दी. भाजपा 21 सीटों पर ही सिमट कर रह गयी। इंडिया गठबंधन के इस ज्वार में प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी हार गये. वह चंदनकियारी से तीसरे स्थान पर रहे, उनसे ज्यादा वोट जेएलकेएम को आया. 10 सीटों पर लड़नेवाली आजसू पार्टी मांडू की

एक सीट जीत पायी. जयराम महतो खुद डुमरी से जीत गये। लेकिन कैंची ने भाजपा और आजसू को एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर डैमेज किया। एनडीए की हार की वजह जेकेएलम बना. लोजपा और जदयू एक–एक सीट जीत कर आये। लेकिन यह एनडीए को सत्ता तक पहुंचाने के लिए किसी काम का नहीं है। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार की ओर से लागू मंईयां सम्मान योजना गेम चेंजर बनी. आधी आबादी ''इंडिया गठबंधन'' के साथ चली. वहीं, भाजपा का ''बांग्लादेशी घुसपैठ'' वाला नैरेटिव और गोगो दीदी योजना का 21 सौ रुपये देनेवाली घोषणा रंग नहीं ला पाया।

झारखण्ड विधानसभा चुनाव (2024) में झामुमो एवं गठबंधन की जीत का मुख्य कारण निम्नलिखित है। [18]

(क) हेमंत सोरेन और आदिवासी पहचान
हेमंत सोरेन को जब जनवरी 2024 में जेल हुआ और बाद में जमानत मिली, तब जेएमएम ने इसे आदिवासी समुदाय के सम्मान से जुड़ा मामला बताया। इससे आदिवासी वोटरों में सहानुभूति और समर्थन मजबूत हुआ, जो झारखंड के करीब 26% आबादी का बड़ा हिस्सा है।

(ख) लोक–हितैषी कल्याण योजनाएँ
इंडिया गठबंधन ने कई स्थानीय सामाजिक और वित्तीय योजनाएँ जोर से प्रचारित कीं, जिनका प्रभाव वोटरों पर इस प्रकार रहा। **माईया सम्मान योजना के तहत** महिलाओं को प्रतिमाह नकद सहायता (आरंभ में 1,000, बाद में 2,500 रूपये तक) का वादा/विस्तार, जिससे खासकर ग्रामीण और महिलाएँ आकर्षित हुईं। **पेंशन योजनाओं का विस्तार करके** वृद्ध, विकलांग और विशेष जरूरत समूहों के लिए पेंशन राशि और लाभ का विस्तार किया गया। बिजली बिल माफी और मुफ्त इकाई के अंतर्गत कम–आय वाले ग्रामीण और उपभोक्ताओं का भारी समर्थन इससे मिला। अबुआ **आवास योजनाएँ के तहत** गरीबों को अधिक मदद तथा तीन कमरों के घर के लिए ज्यादा अनुदान देने की घोषणा से भी स्थानीय समर्थन बढ़ा।

(ग)_समुदायों के बीच गठबंधन और वोट साझा करना कारगर साबित हुआ। झामुमो के साथ कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई (एमएल)–लिबरेशन का गठबंधन (इंडिया ब्लॉक) सामाजिक समूहों जैसे आदिवासी–मुस्लिम–गरीब वोटरों को एक मंच पर जोड़ने में सफल रहा। इससे वोट शेयर और सीटों पर बढ़त मिली।

(घ) बीजेपी की रणनीति का सीमित असर रहा है।

1. भाजपा की चुनावी रणनीति में कुछ चुनौतियाँ रही
2. **मुख्य मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्ट न होना** – पार्टी ने राज्य में स्पष्ट नेतृत्व चेहरे को उभारने में सफलता नहीं पाई।
3. **'आतंकवाद/बांग्लादेशी घुसपैठ'' जैसे मुद्दों का कमजोर असर** – इस तरह के विभाजनकारी तों ने वोटरों को बाँटने में अपेक्षित असर नहीं डाला।
4. **जनवादी और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ कमजोर** – स्थानीय हित और कल्याण योजनाओं से जुड़ा एजेंडा ज्यादा असरदार रहा।

(ङ) आदिवासी वोट में जेएमएम का मजबूत असर रहा है।
झामुमो ने बीजेपी की पारंपरिक आदिवासी वोट बैंक को फिर से अपने पक्ष में कर लिया और अधिकांश एसटी आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की, जिससे गठबंधन की जीत की संख्या बढ़ी।

झारखण्ड विधानसभा चुनाव (2024) में भाजपा एवं गठबंधन की हार के कारण [19]

(क) ट्राइबल वोट (आदिवासी वोट) में भारी नुकसान हुआ। भाजपा 2024 में आदिवासी समुदाय का समर्थन बरकरार रखने में असफल रही। जनजातिय क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और अधिकांश एसटी–आरक्षित सीटों पर जेएमएम–गठबंधन ने बढ़त बनाई। इससे राज्य का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक भाजपा से हट गया। आदिवासी मतदाता भाजपा की ''हिन्दुत्व''–केंद्रित रणनीति या उनकी मुखर नीतिगत प्रतिबद्धता से संतुष्ट नहीं दिखे, और जेएमएम जैसे क्षेत्रीय दलों को ज्यादा भरोसेमंद माना।

(ख) स्थानीय मुद्दों और विकास एजेंडा का भी कमजोर असर रहा है। भाजपा का चुनावी प्रचार ''राष्ट्रीय मुद्दों'' या विभाजनकारी रणनीतियों पर अधिक केंद्रित रहा, जैसे **आप्रवासन/नागरिकता–संबंधी चिंताएँ,** लेकिन ये झारखंड जैसे राज्य में उतना प्रभावी नहीं रहा। झामुमो–गठबंधन ने स्थानीय विकास योजनाओं, कल्याण नीतियों और प्रत्यक्ष लाभ वाले मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया।

भाजपा के ''बांग्लादेशी घुसपैठ'' जैसे संदेश ने अपेक्षित वोट बैंक को आकर्षित नहीं किया। इसका असर यह हुआ कि स्थानीय समस्याओं पर भाजपा की पकड़ कमजोर दिखी और वोटरों का फोकस जमीनी कल्याण योजनाओं की तरफ रहा।

(ग) इंडिया गठबंधन का मजबूत स्थानीय गठजोड़ सफल रहा है। भाजपा की हार का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि **जेएमएम–कांग्रेस–राजद** गठबंधन ने स्थानीय स्तर पर प्रभावी गठबन्धन बनाया। यह गठबंधन आदिवासी, ओबीसी और ग्रामीण वोटर्स को जोड़ने में सफल हुआ, जिससे भाजपा के वोट शेयर पर प्रत्यक्ष असर पड़ा। इस तरह के गठजोड़ ने भाग को विभाजित वोटों के कारण कमजोर किया।

(घ) भाजपा संगठनात्मक और रणनीतिक चुनौतियॉ विद्यमान रही। भाजपा को झारखंड में **अंदरूनी गुटबाजी** और संगठनात्मक कमजोरी का भी सामना करना पड़ा।
पार्टी की स्थानीय इकाई में गुटबाज़ी और नेतृत्व मुद्दे सामने आए। स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका को ठीक से पेश नहीं किया जा सका।

(ङ) प्रत्यक्ष आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर मतदान की प्राथमिकता बनी रही। भाजपा के मुकाबले विपक्ष ने लाभार्थी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा और प्रत्यक्ष आर्थिक राहत पर जोर दिया, जो ग्रामीण और मध्यम–आय वर्ग के वोटरों को आकर्षित कर सकीं। इसे पत्रकारों और विश्लेषकों ने भाजपा की हार के एक कारण के रूप में उद्धृत किया है।

(च)भाजपा की चुनावी रणनीति की सीमाएँ यह थी कि भाजपा **ने** स्थानीय स्तर पर स्थिर मुद्दों पर ज्यादा जोर नहीं दिया। प्रचार और संदेश को अनुकूलित करने में समय रहते बदलाव नहीं किए। स्थानीय नीतिगत चिंताओं को राष्ट्रीय नरेटिव से ऊपर नहीं रखा। इन कारणों से भी भाजपा की पकड़ कमजोर पड गई। भाजपा की हार के मुख्य कारण थे। आदिवासी वोटों का टूटना, स्थानीय विकास और कल्याण नीतियों में कमजोर असर, मजबूत इंडिया गठबंधन का प्रभाव, संगठनात्मक गुटबाज़ी और रणनीति की कमज़ोरियाँ और विभाजनकारी संदेश का अपेक्षित असर न होना।

निष्कर्ष

झारखंड की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को राज्य की बागडोर सौंप दी है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि झारखंड गठन के बाद पहली बार कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रही है। हेमंत सोरेन को जनता ने ऐसा बहुमत सौंपा है, जो इसके पहले किसी अन्य गठबंधन को हासिल नहीं हुआ है. निश्चित तौर पर झारखंड के आदिवासी समुदाय और हाशिए पर छूटे लोगों ने हेमंत सोरेन पर पूरा भरोसा जताया है। हेमंत सोरेन से जनता की भारी अपेक्षाएं हैं और उनके समक्ष इन पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है। जनता की अपेक्षा है कि हेमंत सोरेन प्रभावी और साफ सुथरा प्रशासन देंगे। जल, जंगल, जमीन में झारखंड की आत्मा बसती हैं। उनके सामने इसे सहेजने का अवसर है, इस बार विपक्ष खास कर भाजपा बहुत कमजोर है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है. उम्मीद है कि विपक्ष राज्य के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। यह हम सब जानते हैं कि आज झारखंड को जहां होना चाहिए था, आज वह वहां नहीं है। विगत 24 वर्षो में विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए थी वैसी नहीं रही है। लोगों को उम्मीद है कि हेमंत झारखंड के विकास को नयी रफ्तार देंगे। आम आदमी की तीन बुनियादी जरूरतें हैं– बिजली, पानी और सड़क, इन तीनों क्षेत्रों में अभी बहुत काम करना बाकी है, प्रकृति झारखंड पर मेहरबान रही है। प्रकृति ने इतना खनिज देश के किसी अन्य राज्य को नहीं दिया है. इन खनिजों का दोहन तो होता है, लेकिन इसका पूरा लाभ न तो राज्य को मिल पाता है और न ही यहां के लोगों को. इन खनिजों पर आधारित उद्योग झारखंड में लगे, तभी राज्य को लाभ मिल पाएगा। झारखंड के बड़े हिस्से में सिंचाई की सुविधा नहीं है। सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम करना होगा। झारखंड में सब्जी–फलों की अच्छी खेती होती है। यहां की सब्जी कोलकाता और मुंबई तक जाती है। परन्तु इसका लाभ किसानों को न मिलकर बिचौलियों को मिलता है। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और यूनिट को लगाने से किसानों का भाग्य बदल जायेगा। दो अन्य क्षेत्रों –शिक्षा और स्वास्थ्य। राज्य के लोगों को पढ़ाई और चिकित्सा के लिए दक्षिण भारत

जाना पड़ता है. अगर झारखंड को ही शिक्षा और स्वास्थ्य को केन्द्र एजुकेशन के रूप में विकसित किया जाये, तो राज्य की तस्वीर बदल सकती है।

संदर्भ सूची

1.http//eci.gov.in

2.http//eci.gov.in

3. ई–पेपर प्रभात खबर, राँची, 24.11.2024

4. ई–पेपर प्रभात खबर, राँची,24.11.2025

5. ई–पेपर प्रभात खबर, राँची, 21.11.2024

6. ई–पेपर हिन्दुस्तान, राँची,24.11.2024

7. ई–पेपर हिन्दुस्तान, राँची, 26.11.2024

8. ई–पेपर प्रभात खबर, राँची,27.11.2024

9. ई–पेपर प्रभात खबर, राँची,26.11.2024

10. ई–पेपर हिन्दुस्तान, राँची,27.11.2024

11. ई–पेपर प्रभात खबर, राँची,25.11.2024

12. ई–पेपर प्रभात खबर, राँची,25.11.2024

13. ई–पेपर प्रभात खबर, राँची, 24.11.2024

14. ई–पेपर दैनिक जागरण, राँची,25.11.2024

15. ई–पेपर दैनिक जागरण, राँची, 25.11.2024

16. ई–पेपर दैनिक जागरण, राँची, 27.11.2024

17. http//eci.gov.in

18. ई–पेपर हिन्दुस्तान, राँची,29.11.2024

19. ई–पेपर हिन्दुस्तान, राँची,29.11.2024